सामान्य अध्ययन

भारतीय अर्थव्यवस्था

CSE पाठ्यक्रम के अनुरूप

Powered by

Sanskriti IAS

भारतीय अर्थव्यवस्था

विषय-सूची

इकाई	टॉपिक	पृष्ठ संख्या
1	अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र : एक परिचय	3-8
2	वित्तीय प्रणाली	9-54
3	मुद्रास्फीति	55-63
4	राष्ट्रीय आय का लेखांकन	64-75
5	वैदेशिक क्षेत्र	76-114
6	लोक वित्त	115-149
7	अवसंरचना, निवेश और निवेश मॉडल	150-170
8	भारतीय कृषि	171-225
9	समावेशी विकास	226-256
10	उद्योग	257-275
11	व्यष्टि अर्थशास्त्र	276-289
12	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	290-308
13	पूंजी बाज़ार	309-331
14	आयोजन	332-344
15	सतत् विकास	345-352

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 1 — अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र : एक परिचय (Economy and Economics : An Introduction)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र : एक परिचय तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अर्थशास्त्र क्या है
- अर्थव्यवस्था क्या है
- अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में संबंध
- उत्पादन के कारक
- प्रमुख आर्थिक क्रियाएँ
- अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण
- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
- व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर
- समष्टि दृष्टिकोण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
- आय का चक्रीय प्रवाह

अर्थशास्त्र क्या है (What is Economics)

अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, बचत, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोज़गार के अवसर तथा जीवन-गुणवत्ता इत्यादि से संबंधित विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' में इसे 'धन का विज्ञान' कहा है।

अर्थव्यवस्था क्या है (What is Economy)

अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का एक व्यावहारिक पक्ष है जिसमें व्यक्ति, समाज, क्षेत्र और देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसका उपयोग किसी देश में उपलब्ध संसाधनों के दोहन, नवीन संसाधनों के निर्माण तथा नागरिकों के अधिकतम सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए किया जाता है।

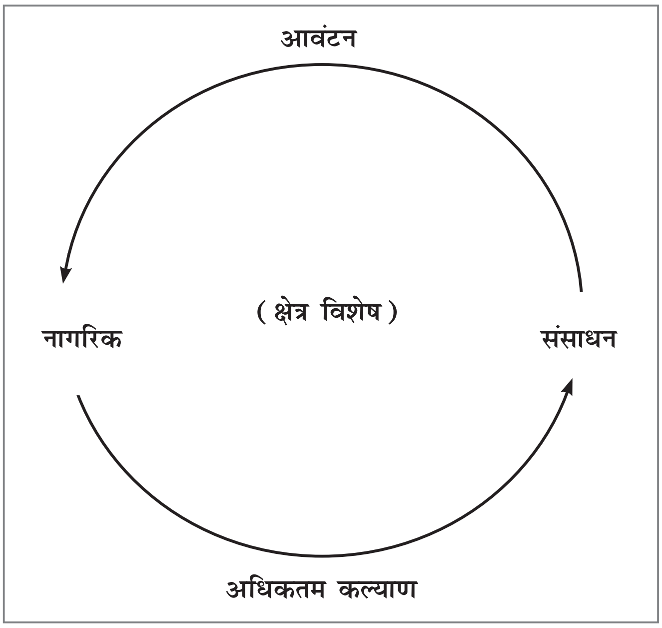

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में संबंध (Relation between Economics and Economy)

यदि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों की बात करें तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका व्यावहारिक पक्ष। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों एवं नियमों की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था क्षेत्र विशेष में इन सिद्धांतों व नियमों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर है।

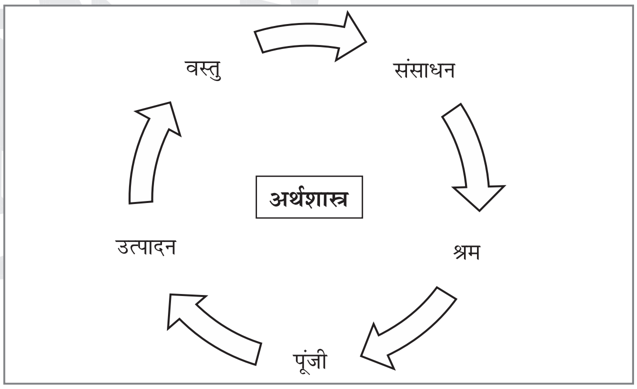

उत्पादन के कारक (Factors of Production)

वे सभी कारक जिनके माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है, उत्पादन के कारक कहलाते हैं। ये मुख्यत: चार प्रकार के होते हैं-

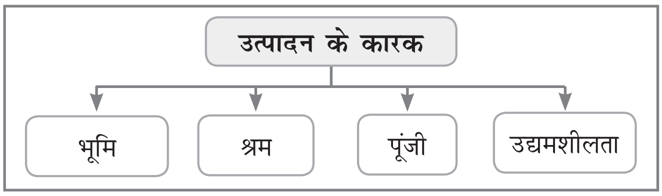

भूमि (Land)

- यह प्रकृति से प्राप्त नि:शुल्क उपहार है।
- इसकी आपूर्ति सीमित है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 2 — वित्तीय प्रणाली (Financial System)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'वित्तीय प्रणाली तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- वित्त
- वित्तीय प्रणाली
- वित्तीय प्रणाली का महत्त्व
- वित्तीय प्रणाली के अवयव
- वित्तीय बाज़ार
- मुद्रा बाज़ार
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

मौद्रिक नीति

- परिचय
- मौद्रिक नीति के प्रकार
- मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य
- मौद्रिक नीति के उपकरण
- मौद्रिक नीति संचरण
- मौद्रिक नीति के अन्य उपकरण
- मौद्रिक नीति की समीक्षा में संस्थागत सुधार
- मौद्रिक नीति की सीमाएँ

बैंकिंग

- परिचय
- प्रमुख बैंकिंग व्यवस्थाएँ
- बैंकों के प्रकार
- अनुसूचित बैंक
- एकीकृत लोकपाल योजना
- एन.बी.एफ.सी. अकाउंट एग्रीगेटर
- वित्तीय समावेशन
- जमा बीमा योजना

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ

- परिसंपत्ति
- परिसंपत्तियों के प्रकार
- उच्च एन.पी.ए. के लिए उत्तरदायी कारक
- एन.पी.ए. के प्रभाव
- एन.पी.ए. के समाधान हेतु उपाय
- रिज़र्व बैंक के ऋण समाधान मानक
- एन.पी.ए. की स्थिति

बैंकिंग सुधार एवं मुद्रा

- बेसल मानक
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार
- पूंजी संरक्षण बफर
- साख-पत्र
- लेटर ऑफ अंडरटेकिंग
- स्विफ्ट
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
- वास्तविक समय सकल निपटान
- तत्काल भुगतान सेवा
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
- भीम ऐप
- ई-रुपी
- भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट
- मर्चेंट डिस्काउंट दर
- लीवरेज कवरेज अनुपात
- तरलता कवरेज अनुपात
- टोकनाइज़ेशन
- टीज़र लोन
- एस्क्रो खाता
- व्हाइट लेबल ए.टी.एम.
- आभासी बैंकिंग सिस्टम
- मुद्रा
- डिजिटल मुद्रा
- बैंकिंग सुधार से संबंधित समितियाँ
- बैंकों का विलय
- प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक
- विमुद्रीकरण
- RBI की प्रमुख पहलें

वित्त (Finance)

सरल रूप में धन या कोष का प्रबंधन वित्त कहलाता है। वित्त से संबंधित दो प्रमुख अवधारणाएँ हैं-

- वित्तीय लेनदेन की क्रियाओं को वित्तीय विनिमय कहा जाता है।
- ऐसी संस्थागत व्यवस्था जहाँ क्रेता और विक्रेता वित्त का लेनदेन करते हैं, वित्तीय बाज़ार कहलाती है।

वित्तीय प्रणाली (Financial System)

वित्तीय प्रणाली वस्तुत: वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उपकरणों एवं वित्तीय बाज़ार का सम्मिलित रूप है जहाँ सुचारु रूप से वित्त के आदान-प्रदान की सुविधा उपलब्ध होती है। मांग एवं आपूर्ति वित्तीय प्रणाली के दो मुख्य घटक हैं।

वित्तीय प्रणाली का महत्त्व (Importance of Financial System)

वित्तीय प्रणाली का महत्त्व निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है-

- देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का इष्टतम व कुशलतम उपयोग करके अधिकतम लाभ अर्जित करना।
- वित्तीय प्रणाली द्वारा कोष के प्रबंधन एवं कोष वृद्धि के लिए उपाय भी किए जाते हैं।
- उत्पादन के कारकों (भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता) की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- लाभांश का वितरण भी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से संभव है।

Copyright @ Sanskriti IAS

- यह शिकायत निवारण को सरल एवं सुलभ बनाता है।
- इसके माध्यम से बैंकों और ग्राहकों के बीच विश्वासपूर्ण संबंध मज़बूत होने से सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

एन.बी.एफ.सी. अकाउंट एग्रीगेटर (NBFC Account Agrigator - AA)

- यह आर.बी.आई. द्वारा विनियमित एक ऐसी इकाई है जो किसी व्यक्ति को सुरक्षित व डिजिटल रूप में एक वित्तीय संस्थान से प्राप्त अपने खाते की जानकारी को अकाउंट एग्रीगेटर में शामिल किसी अन्य वित्तीय संस्थान के साथ साझा करने में मदद करती है। अर्थात्, इसके तहत व्यक्ति की सहमति के बिना डाटा को साझा नहीं किया जा सकता है।
- अकाउंट एग्रीगेटर (फाइनेंशियल डाटा एग्रीगेटर) एक वेब आधारित प्रणाली है जो विभिन्न अकाउंट, यथा- बैंक अकाउंट तथा क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि से संबंधित जानकारियों का संग्रहण करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2016 में अकाउंट एग्रीगेटर को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) का दर्जा प्रदान किया।

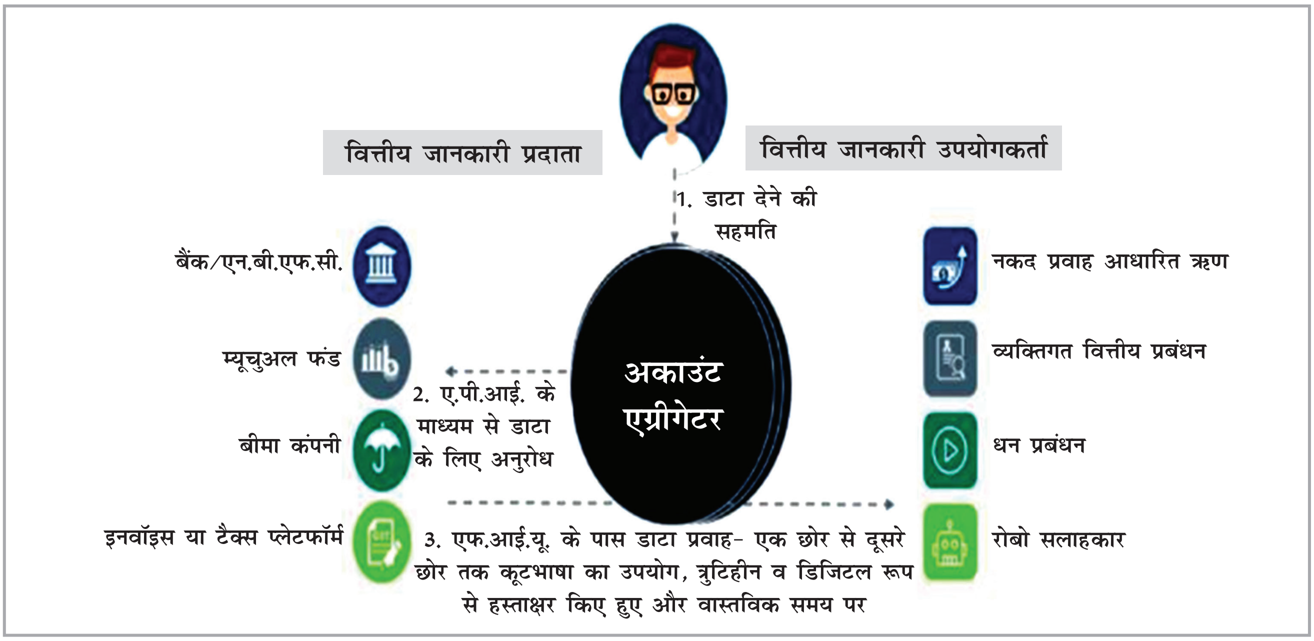

लाभ (Benefits)

- यह भारत में ओपन बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने की दिशा में पहला कदम है, जो लाखों ग्राहकों को सुरक्षित और कुशल तरीके से अपने वित्तीय डाटा तक डिजिटल रूप में पहुँचने तथा इसे अन्य संस्थानों के साथ साझा करने के लिए सशक्त बनाता है।
- बैंकिंग में अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली, भारत के आठ सबसे बड़े बैंकों के साथ शुरू की गई है। यह ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज़ और किफायती बना सकता है।
- यह डाटा के प्रत्येक उपयोग के लिए 'रिक्त चेक' स्वीकृति के लंबे नियम तथा शर्तों के बदले एक संक्षिप्त, चरण-दर-चरण अनुमति और नियंत्रण का प्रस्ताव देता है।
- यह डाटा को स्टोर नहीं कर सकता है।
- यह किसी ग्राहक के डाटा को पढ़ या कॉपी नहीं कर सकता है।
- यह डाटा को लाभ के लिए दूसरों को दोबारा बेच भी नहीं सकता है।
- यह नए ग्राहकों को यह सुविधा देता है कि वे चयन के आधार पर डाटा को साझा करें। हालाँकि, ग्राहक साझा किए गए डाटा को वापस भी ले सकता है।
- यह ग्राहकों के प्रति ज़िम्मेदार होता है, जिन्हें आर.बी.आई. द्वारा विनियमित किया जाता है तथा जो डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए एवं कूटभाषा का इस्तेमाल करते हुए डाटा साझा करते हैं।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

- वित्तीय समावेशन से अभिप्राय समाज के कमज़ोर वर्गों और कम आय वाले समूहों की वित्तीय सेवाओं, जैसे- बचत खाता, कम लागत वाले ऋण, वित्तीय सलाहकार और बीमा सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है।
- यह समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 3	मुद्रास्फीति (Inflation)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'मुद्रास्फीति तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- फिलिप्स वक्र
- मुद्रास्फीति के प्रकार
- मुद्रास्फीति के कारण
- व्यापार चक्र
- मुद्रा अवस्फीति/मुद्रा संकुचन

मुद्रास्फीति की गणना
- परिचय
- कीमत सूचकांक विधि
- जी.डी.पी. अवस्फीतिकारक
- एन.एच.बी. रेज़ीडेक्स

- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु उपाय
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
- ऑपरेशन ग्रीन्स
- मूल्य स्थिरीकरण निधि
- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)

परिचय (Introduction)

- मुद्रास्फीति से तात्पर्य उस स्थिति से है जब एक निश्चित अवधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से अधिक की वृद्धि होने लगती है।
- इस स्थिति में मुद्रा की क्रय-शक्ति घटने लगती है क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है।
- कीन्स के अनुसार, मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में अंतर का परिणाम है।

फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)

वर्ष 1958 में ए.डब्ल्यू. फिलिप्स ने मौद्रिक मज़दूरी में परिवर्तन की दर या स्फीति की दर तथा बेरोज़गारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखा, जिसे एक वक्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस वक्र को ही 'फिलिप्स वक्र' कहते हैं। इसके अनुसार, मुद्रास्फीति दर एवं बेरोज़गारी दर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात्

$$\text{मुद्रास्फीति दर} \propto \frac{1}{\text{बेरोज़गारी दर}}$$

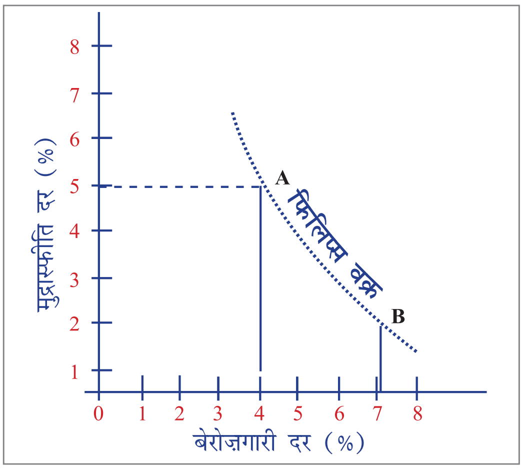

ज्ञातव्य है कि फिलिप्स वक्र के संबंध में आगे चलकर मिल्टन फ्रीडमैन ने यह प्रतिपादित किया कि मुद्रास्फीति दर एवं बेरोज़गारी दर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध केवल अल्पकाल के लिए ही सत्य है, दीर्घकाल में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का रोज़गार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा बेरोज़गारी का एक स्तर बना रहेगा।

मुद्रास्फीति के प्रकार (Types of Inflation)

मुद्रास्फीति मूलतः दो प्रकार की होती है–

मांग-जनित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation)

जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग, आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ने लगती है तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है, इसे मांग-जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति उनकी मांग के सापेक्ष कम होती है।

लागत-जनित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation)

जब वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे लागत-जनित मुद्रास्फीति कहते हैं।

मुद्रास्फीति के कारण (Causes of Inflation)

मांग आधारित कारण

- जनसंख्या वृद्धि
- रोज़गार, मज़दूरी एवं आय में वृद्धि
- शहरीकरण का बढ़ता दायरा
- काला धन
- सरकारी व्यय में वृद्धि

आपूर्ति आधारित कारण

- अनियमित खाद्य आपूर्ति
- औद्योगिक उत्पादन में कमी
- वस्तुओं की जमाखोरी
- आयात पर नियंत्रण
- अवसंरचनात्मक बाधाएँ

अन्य कारण

- प्राकृतिक आपदा
- औद्योगिक इकाइयों के खराब प्रबंधन
- अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या वैश्विक महामारी
- कार्टेलाइज़ेशन प्रथाएँ

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 4 — राष्ट्रीय आय का लेखांकन (Accounting of National Income)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'राष्ट्रीय आय का लेखांकन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- राष्ट्रीय आय
- राष्ट्रीय आय से संबंधित शब्दावलियाँ
- आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर
- राष्ट्रीय आय और आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक
- राष्ट्रीय आय में लागत/मूल्य संबंधी संकल्पनाएँ
- राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएँ
- राष्ट्रीय आय का मापन
- राष्ट्रीय आय के मापन में समस्याएँ
- आय से संबंधित अन्य संकल्पनाएँ
- कोर उद्योग
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- मानव विकास सूचकांक
- सकल राष्ट्रीय खुशहाली
- वी-आकार का आर्थिक सुधार

राष्ट्रीय आय (National Income)

- आर्थिक संकल्पनाओं में राष्ट्रीय आय एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। किसी भी देश के आर्थिक आकार एवं स्वरूप को समझने के लिए राष्ट्रीय आय को समझना आवश्यक है।
- राष्ट्रीय आय एक लेख वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है।
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (National Statistical Office - NSO) द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

- मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office) का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office - NSO) नामक नई एजेंसी का सृजन किया गया। इसका गठन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है।
- इसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक द्वारा की जाती है। यह अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- इसके द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) आदि पर देशव्यापी घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से डाटा एकत्र किया जाता है।
- इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, एन.एस.ओ. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कीमतों के बारे में डाटा एकत्र करता है तथा संबंधित राज्य एजेंसियों की क्षेत्र गणना एवं फसल आकलन सर्वेक्षणों की निगरानी के माध्यम से फसल के आँकड़ों के सुधार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय आय से संबंधित शब्दावलियाँ (Terminologies related to National Income)

मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods)

मध्यवर्ती वस्तुएँ वे हैं जिन्होंने अभी तक उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, मध्यवर्ती वस्तुएँ वे हैं जिन्हें एक फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म से पुन: बिक्री के लिए अथवा कच्चे माल या आगत (Input) के रूप में प्रयोग हेतु खरीदा जाता है।

अंतिम वस्तुएँ (Final Goods)

वे वस्तुएँ जो उत्पादन की सीमा-रेखा अथवा प्रक्रिया को पार कर चुकी हैं और अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं, 'अंतिम वस्तुएँ' कहलाती हैं।

नोट : जी.डी.पी. की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, अर्थात् इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता।

कारक/साधन आय (Factor Income)

उत्पादक इकाइयों (फर्मों) द्वारा परिवारों/व्यक्तियों (उत्पादन के कारकों के स्वामी) को उनकी कारक सेवाओं के बदले किया गया भुगतान 'कारक आय' होता है। यह एक द्विपक्षीय भुगतान है। जैसे–

- भूमि से प्राप्त लगान/किराया (Rent)
- श्रम के बदले कर्मचारियों को प्राप्त पारिश्रमिक (Wage)
- पूंजी से प्राप्त ब्याज (Interest)
- उद्यमशीलता से प्राप्त लाभ (Profit)

हस्तांतरण आय (Transfer Income)

- वह आय जो सरकार से सहायता या सब्सिडी के रूप में प्राप्त होती है, उसे हस्तांतरण आय कहते हैं।
- यह एकपक्षीय भुगतान होता है।
- यह अनर्जित आय होती है। यह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन का परिणाम नहीं होती है।

Copyright @ Sanskriti IAS

राष्ट्रीय आय और आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक (Factors affecting National Income and Economic Growth)

मानव संसाधन (Human Resource)

किसी देश की जनसंख्या जितनी अधिक कुशल होगी, उसकी उत्पादन क्षमता निश्चित रूप से अधिक होगी।

प्राकृतिक संसाधन (Natural Resource)

प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, मृदा की गुणवत्ता, वन संपदा, खनिज एवं तेल संसाधन इत्यादि शामिल होते हैं। जो देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से जितना अधिक समृद्ध होगा, उसकी राष्ट्रीय आय व आर्थिक संवृद्धि दर में उतनी ही वृद्धि होगी।

पूंजी निर्माण (Capital Formation)

किसी भी देश की आर्थिक संवृद्धि के लिए अनिवार्य एवं आधारभूत शर्त है– उस देश में पूंजी निर्माण हो। जिस देश में जितनी अधिक पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है, उस देश में आर्थिक संवृद्धि की संभावना उतनी ही अधिक होती है। पूंजी निर्माण से प्रति श्रमिक पूंजी की उपलब्धता बढ़ती है जो पूंजी-श्रम अनुपात को और बढ़ाती है।

बचत दर और निवेश दर (Saving Rate and Investment Rate)

बचत दर में वृद्धि से पूंजी निर्माण (निवेश) में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, एक ओर जहाँ उत्पादन में वृद्धि होने से गरीबी और बेरोज़गारी में कमी आती है, वहीं उपभोग में वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी ओर, निवेश में वृद्धि के कारण जी.डी.पी. में वृद्धि होती है और संभाव्य आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। संवृद्धि का सुचक्र इस प्रकार है–

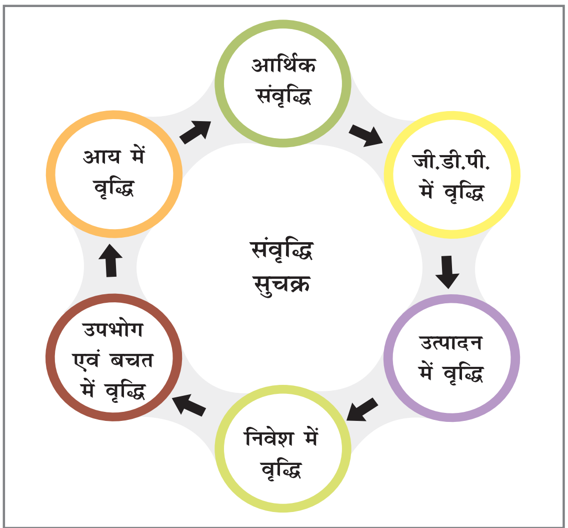

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

तकनीकी विकास से पूंजी निर्माण को भी बल मिलता है क्योंकि इससे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। गौरतलब है कि उच्च तकनीकी प्रयोग द्वारा अल्प संसाधन की सहायता से भी उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि उन्नत तकनीक संसाधनों के दोहन में सुधार लाती है।

सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति (Social and Political Situation)

पारंपरिक मान्यताओं व अंधविश्वासों वाला समाज जीवन जीने के आधुनिक तरीकों को अपनाने का विरोध करता है। जिस देश में राजनीतिक स्थिरता रहती है, उस देश के विकास की गति तीव्र होती है। एक स्थिर, कुशल एवं व्यवस्थित शासन वाली सरकार निवेशकों को आकर्षित करती है, फलस्वरूप देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

उद्यमशीलता एवं नवाचार (Entrepreneurship and Innovation)

संसाधनों से आय का अर्जन स्वयं ही नहीं हो जाता है, बल्कि इसके लिए उन संसाधनों में मानव अपनी उद्यमशीलता तथा रचनात्मक दक्षता का प्रयोग करके उन्हें उपयोगी एवं लाभकारी बनाता है।

पूंजी-उत्पाद अनुपात (Capital-Output Ratio)

पूंजी-उत्पाद अनुपात से तात्पर्य प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा से है। यदि पूंजी-उत्पाद अनुपात अधिक है तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उच्च बचत होने के बाद भी पूंजी निर्माण, उच्च वृद्धि दर में परिवर्तित नहीं हो पाता है। जिस देश में यह अनुपात जितना कम होगा, वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

जब सभी लोगों की वित्तीय संस्थाओं तक पहुँच होगी तो उनके बचत में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है जिससे आर्थिक संवृद्धि में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय आय में लागत/मूल्य संबंधी संकल्पनाएँ (Concepts related to Cost/Price in National Income)

साधन/कारक लागत (Factor Cost)

- भूमि, श्रम, उद्यमशीलता एवं पूंजी को उत्पादन के साधन कहा जाता है और इन उत्पादन के साधनों पर जो व्यय होता है, उसे ही कारक लागत (Factor Cost) कहते हैं। वास्तविक उत्पादन लागत वह है जिस पर किसी फर्म द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।
- साधन लागत की गणना करते समय बाज़ार मूल्य में से निवल अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी) को घटा दिया जाता है।

साधन लागत = बाज़ार मूल्य – निवल अप्रत्यक्ष कर (NIT)

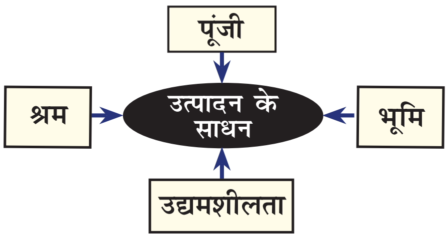

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 5 — वैदेशिक क्षेत्र (Foreign Sector)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'वैदेशिक क्षेत्र तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय

भुगतान संतुलन
- परिचय
- भुगतान संतुलन का महत्त्व
- भुगतान संतुलन की संरचना
- भुगतान शेष में असंतुलन
- सरकारी निधि/कोष खाता
- बाह्य वाणिज्यिक उधार

विदेशी विनिमय दर
- परिचय
- विदेशी विनिमय बाज़ार
- विदेशी विनिमय दर प्रणालियाँ
- विदेशी विनिमय पर नियंत्रण
- मुद्रा का मूल्यह्रास
- मुद्रा का अवमूल्यन
- उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली
- मुद्रा की परिवर्तनीयता
- पूंजी खाते पर मुद्रा की परिवर्तनीयता
- विदेशी विनिमय भंडार
- रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण
- विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता
- डी-डॉलरीकरण

नई आर्थिक नीति
- आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि
- आर्थिक संकट के कारण
- नई आर्थिक नीति के उद्देश्य
- उदारीकरण
- निजीकरण
- वैश्वीकरण
- नई आर्थिक नीति की उपलब्धियाँ
- आर्थिक सुधारों के नकारात्मक पक्ष

विदेशी व्यापार
- परिचय
- विदेशी व्यापार का महत्त्व
- विदेशी व्यापार से संबंधित शब्दावलियाँ
- भारत के विदेशी व्यापार की संरचना
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल
- भारत के विदेशी व्यापार की समस्याएँ
- भारत में आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्द्धन
- एक्ज़िम बैंक
- विदेशी व्यापार नीति, 2023
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, 2000
- तटीय आर्थिक क्षेत्र
- औद्योगिक गलियारे
- क्षेत्रीय व्यापार समझौते
- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता एवं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी
- विदेशी निवेश

परिचय (Introduction)

- वैदेशिक क्षेत्र में वह सब कुछ शामिल है जो किसी देश की सीमाओं से परे है। यह देश की अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो विदेशी व्यापार (आयात और निर्यात) और पूंजी प्रवाह से संबंधित है।
- घरेलू अर्थव्यवस्था और विदेशी क्षेत्र के बीच सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक अंतर्संबंध विदेशी व्यापार है।
- घरेलू परिवार, व्यवसाय और सरकारी क्षेत्र विदेशी क्षेत्र से आयात करते हैं। विदेशी क्षेत्र, घरेलू व्यापार क्षेत्र से आयात करता है।
- वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार, विदेशी विनिमय दर, विदेशी निवेश आदि का अध्ययन किया जाता है।

भुगतान संतुलन (Balance of Payments)

परिचय (Introduction)

- भुगतान संतुलन सामान्यत: एक वर्ष में किसी देश द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ किए जाने वाले मौद्रिक लेनदेन का व्यवस्थित विवरण है, अर्थात् भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतया एक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार/लेनदेन का विवरण होता है।
- ज्ञातव्य है कि भुगतान संतुलन किसी देश की अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन स्थिति पर प्रकाश नहीं डालता है।
- भुगतान संतुलन के मौद्रिक लेनदेन में वस्तुओं के आयात-निर्यात, सेवाओं के निर्यात एवं आयात, वित्तीय परिसंपत्तियों, बॉण्ड्स, वास्तविक परिसंपत्तियों तथा मशीनरी आदि लेनदेन को जिस खाते में दर्ज किया जाता है, उसे ही 'भुगतान संतुलन खाता' (Balance of Payment Account) कहते हैं।
- भुगतान संतुलन (BoP) के अंतर्गत सभी आर्थिक लेनदेन को दो पक्ष में समाहित किया जाता है जिसके लिए द्वि-प्रविष्टि पद्धति (Double entry system) का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्, लेखांकन में दो प्रकार की एंट्री या प्रविष्टि दर्ज की जाती है।

भुगतान संतुलन के लेखांकन की प्रविष्टि

आहरण प्रविष्टि (Debit)	जमा प्रविष्टि (Credit)
• जिस संव्यवहार से विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है उसे आहरण प्रविष्टि में रखा जाता है, यथा- वस्तुओं और सेवाओं का आयात। • इसे ऋणात्मक चिह्न द्वारा दर्शाया जाता है।	• जिस संव्यवहार से विदेशी मुद्रा देश में आती है उसे जमा प्रविष्टि में रखा जाता है, यथा- वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात। • इसे धनात्मक चिह्न द्वारा दर्शाया जाता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

एमनेस्टी योजना (Amnesty Scheme)

- एमनेस्टी योजना के तहत पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल।
- इसका प्रयोजन उन निर्यातकों को राहत प्रदान करना है जो EPCG और अग्रिम प्राधिकरणों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हैं और जो उच्च शुल्क तथा लंबित मामलों से जुड़ी ब्याज लागत के बोझ से दबे हुए हैं।
- इस योजना के तहत अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क के हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, 2000 (Special Economic Zone Policy, 2000)

- भारत, निर्यात संवर्द्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (Export Processing Zone - EPZ) के महत्त्व को स्वीकार करने वाले अग्रणी एशियाई देशों में से था जिसने एशिया का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में वर्ष 1965 में स्थापित किया। कालांतर में 7 और ई.पी.ज़ेड. स्थापित हुए, किंतु प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब, विश्व स्तरीयता के अभाव तथा अनिश्चित एवं अस्थिर राजकोषीय नीतियों के कारण ये निर्यात संवर्द्धन के प्रभावी अस्त्र नहीं बन सके।
- इस प्रकार, उपर्युक्त कमियों पर दृष्टिपात करते हुए भारत में विदेशी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा हुई।
- इस नीति का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना था।
- इसमें उत्तम अवसंरचना, नीतिगत बाधाओं के अल्पीकरण तथा राजकोषीय सुविधाओं पर बल दिया गया।
- इसके अधीन सभी ई.पी.ज़ेड. क्षेत्रों को सेज़ (SEZ) में परिवर्तित कर दिया गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone - SEZ)

- विशेष आर्थिक क्षेत्र/सेज़ (SEZ) किसी देश के अंदर एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे व्यापार तथा शुल्क संबंधी विशेष छूट प्राप्त होती है।
- इस भौगोलिक क्षेत्र से निर्यात, व्यापार, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है।
- सेज़ प्राप्त सुविधाओं एवं स्वायत्तताओं के कारण ही इसे देश में स्थित 'विदेशी क्षेत्र' भी कहा जाता है।

सेज़ अधिनियम, 2005 (SEZ Act, 2005)

सेज़ नीति, 2000 को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 पारित किया जिसे फरवरी 2006 में प्रवर्तित किया गया।

सेज की विशेषताएँ

- लोक-निजी सहभागिता पर आधारित
- शुल्क मुक्त क्षेत्र
- व्यापार, शुल्क तथा टैरिफ की दृष्टि से देश के भीतर विदेशी क्षेत्र
- घरेलू सीमा से वस्तु/सेवा का सेज़ में गमन को आयात, जबकि सेज़ से घरेलू सीमा में आगमित वस्तु/सेवा को निर्यात माना जाता है।
- सेज़ द्वारा खरीदी गई वस्तु केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त होती है।
- सेज़ सेवा कर से भी मुक्त होता है।
- निर्यात-आयात अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त होता है।
- सेज़ में आयात के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता से मुक्ति प्राप्त होती है।
- सेज़ विश्व स्तरीय संरचनात्मक सुविधा-संपन्न होता है।

सेज़ के उद्देश्य

- वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्द्धन
- रोज़गार अवसरों का सृजन
- लालफीताशाही को दूर करना
- निवेश, निर्यात और नियोजन को प्रोत्साहन
- ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना
- घरेलू व विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलाप का सृजन
- अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास
- कर एवं श्रम नीतियों में सुधार
- तीव्र आर्थिक विकास
- विनिर्माण व तकनीकी कौशल का विकास

सेज़ के समक्ष चुनौतियाँ

- अतिशय भूमि अधिग्रहण
- कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव
- किसानों द्वारा विरोध
- राज्य सरकारों द्वारा विरोध
- क्षतिपूर्ति की अपर्याप्तता
- राज्यगत क्षेत्रीय विषमता
- प्रदत्त भारी छूट से सरकारी धन की क्षति
- विस्थापन एवं रोज़गारहीनता में वृद्धि

सेज़ की असफलता के कारण (Causes behind the Failure of SEZ)

- **अवसंरचना का अभाव :** भारत में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण सेज़ पर्याप्त विकास से वंचित रहा है। भारत में पर्याप्त पत्तनों और बंदरगाहों के अभाव, सुदृढ़ एवं निर्बाध परिवहन के अभाव तथा सेज़ के निकट मानवीय आधारभूत संरचनाओं

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 6

लोक वित्त
(Public Finance)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'लोक वित्त तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- लोक वित्त
- लोक वित्त के विषय क्षेत्र
- लोक वित्त का महत्त्व
- लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर
- राजकोषीय नीति
- राजकोषीय नीति के उद्देश्य
- बजट
- बजट के उद्देश्य
- बजट निर्माण की प्रक्रिया
- बजट के घटक
- बजट की विभिन्न स्थितियाँ
- बजट घाटे के प्रकार
- राजकोषीय समेकन
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003
- स्वतंत्र राजकोषीय परिषद्
- हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था
- सार्वजनिक ऋण
- सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी
- राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित मुद्दे
- बजटिंग के प्रकार
- केंद्रीय बजट में किए गए हालिया सुधार
- विनिवेश
- सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने संबंधी उपाय
- 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट
- 16वें वित्त आयोग का गठन

कर व्यवस्था
- कर की अवधारणा
- कराधान के उद्देश्य
- कराधान के सिद्धांत
- कराधान की प्रणाली
- भारतीय कर व्यवस्था
- कर सुधार
- प्रत्यक्ष कर सुधार
- वस्तु एवं सेवा कर
- जी.एस.टी. अपीलीय न्यायाधिकरण
- कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ

लोक वित्त (Public Finance)

- लोक वित्त से तात्पर्य 'जनता के वित्त' अथवा 'सार्वजनिक वित्त' से है। इसके अंतर्गत सरकार के आय-व्यय का अध्ययन किया जाता है तथा इसके माध्यम से यह जाना जाता है कि सरकार कहाँ से एवं किस प्रकार धन का अर्जन करती है तथा उस धन का किस प्रकार व्यय करती है। यहाँ सरकार का तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार से है।
- वर्तमान में लोक वित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है, अब इसमें आय-व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण को भी सम्मिलित किया जाता है।

लोक वित्त के विषय क्षेत्र (Subject of Public Finance)

एडम स्मिथ की पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' (1776) में लोक वित्त के विषय क्षेत्र के रूप में सरकार के राजस्व, व्यय तथा लोक ऋण को बताया गया है। लोक वित्त को निम्नलिखित क्षेत्रों के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है-

- **राजकोषीय या वित्तीय नीति**- स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को गति प्रदान करना
- **सार्वजनिक आय**- सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय
- **सार्वजनिक व्यय**- सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाने वाला पूंजीगत एवं राजस्व व्यय
- **सार्वजनिक ऋण**- बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु लिए गए ऋण
- **वित्तीय प्रशासन**- वित्तीय क्रियाओं के प्रबंधन से संबंधित

लोक वित्त का महत्त्व (Importance of Public Finance)

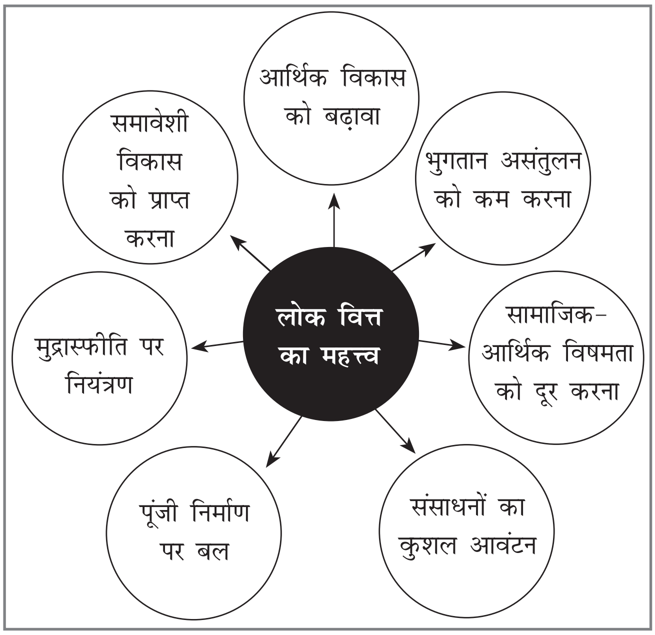

Copyright @ Sanskriti IAS

वास्तव में, यह कर प्रणाली प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होती है।

लेफर वक्र (Laffer Curve)

लेफर वक्र कर राजस्व की प्राप्ति एवं कर की दर के बीच संबंध को व्यक्त करता है, जिसे अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लेफर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें बताया गया है कि यदि कर की दरों को एक सीमा तक बढ़ा दिया जाए तो सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि एक सीमा तक ही होगी तथा इस निश्चित सीमा के बाद कर की दर में वृद्धि से सरकार के राजस्व संग्रह में कमी आने लगेगी। अर्थात् उच्च कर की दर कर अपवंचन को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप काले धन का संचय बढ़ने लगता है।

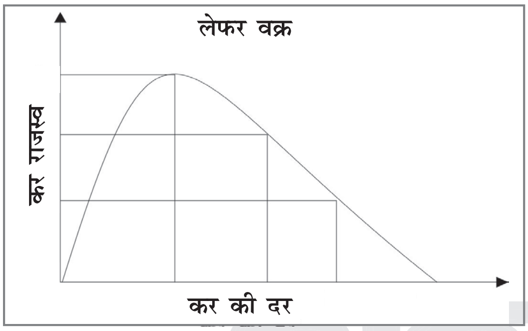

कर के प्रकार (कर के प्रभाव के आधार पर)

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)	अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
• इसके अंतर्गत कराघात एवं करापात एक ही इकाई पर उत्पन्न होता है। • यह उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है, जिस पर उसे कानूनी रूप से अधिरोपित किया जाता है। • इसका कर आधार सीमित है, अतः इससे प्राप्त राजस्व का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। • कर की दर अधिक होने पर कर वंचना बढ़ती है।	• इसके अंतर्गत कराघात तथा करापात अलग-अलग इकाई पर सृजित होता है। • इसका प्रारंभिक भार जिस व्यक्ति पर होता है, अंतिम भार उस व्यक्ति द्वारा वहन नहीं किया जाता है; अर्थात् यह हस्तांतरित किया जा सकता है। • अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर अधिरोपित किए जाते हैं, अतः इनसे प्राप्त राजस्व का अनुमान लगाना कठिन होता है। • कर की दर अधिक होने पर भी कर वंचना नहीं होगी।

कराघात (Impact of Tax)

कराघात, कर का तात्कालिक भार है। कराघात का अनुभव वह व्यक्ति या संस्था करती है जिससे कर का संग्रह किया जाता है।

करापात (Incidence of Tax)

करापात से तात्पर्य कर के अंतिम भार से है। करापात का अनुभव उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अंतिम रूप से कर का अनुभव करता है, अर्थात इसमें देखा जाता है कि कर के भार का मौद्रिक बोझ अंततः किसके ऊपर है।

प्रत्यक्ष कर के गुण (Merits of Direct Tax)	प्रत्यक्ष कर के दोष (Demerits of Direct Tax)	अप्रत्यक्ष कर के गुण (Merits of Indirect Tax)	अप्रत्यक्ष कर के दोष (Demerits of Indirect Tax)
• कर संग्रह का अनुमान लगाना सरल • मितव्ययी • निश्चितता • आर्थिक असमानता में कमी • लोचदार कर व्यवस्था	• सीमित कर आधार • कर अपवंचन की संभावना • असुविधाजनक • कार्य करने, बचत एवं बचत करने की इच्छाओं पर प्रतिकूल प्रभाव	• विस्तृत कर आधार • भुगतान करना सुविधाजनक • कम कष्टदायक • संसाधनों का आवंटन करने में सहायक	• कर संग्रह अनुमान लगाना कठिन • कर वसूलने की प्रशासनिक लागत अधिक • प्रतिगामी प्रभाव (गरीबों पर अधिक) • असमानता में वृद्धि

विशिष्ट कर एवं मूल्यानुसार कर

- वे कर जिन्हें वस्तुओं की इकाई, मात्रा या परिणाम के आधार पर अधिरोपित किया जाता है, विशिष्ट कर कहलाते हैं। जैसे- परिवहन के साधनों के प्रयोग पर लगाया जाने वाला कर।
- वे कर जिन्हें वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, मूल्यानुसार कर कहलाते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग आयात-निर्यात के लिए किया जाता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 7	अवसंरचना, निवेश और निवेश मॉडल (Infrastructure, Investment and Investment Model)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'अवसंरचना, निवेश और निवेश मॉडल तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

अवसंरचना
- परिचय
- आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास में संबंध
- आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रयास
- आधारभूत संरचना विकास की स्थिति
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- आधारभूत संरचना के विकास में चुनौतियाँ
- आधारभूत संरचना के विकास हेतु सुझाव
- भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधारभूत संरचना का महत्त्व

निवेश और निवेश मॉडल
- निवेश
- निवेश के लाभ
- निवेश एवं पूंजी निर्माण के बीच संबंध
- निवेश के प्रकार
- निवेश एवं बचत के बीच संबंध
- बचत के प्रकार
- पूंजी-उत्पाद अनुपात
- मानव पूंजी निर्माण
- निवेश को आकर्षित करने के उपाय
- निवेश मॉडल
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी निवेश मॉडल
- विशेष प्रयोजन वाहन
- व्यवहार्यता/अक्षमता अंतर वित्तपोषण

अवसंरचना (Infrastructure)

परिचय (Introduction)

आधारभूत संरचना (अवसंरचना) वह मूलभूत ढाँचा है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो नही करता, परंतु आर्थिक क्रियाओं (उत्पादन, उपभोग, वितरण) के संपूर्ण संचालन हेतु आवश्यक होता है, अर्थात् आधारभूत संरचना मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र हेतु आधार तैयार करता है, साथ ही देश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करके अर्थव्यवस्था का विकास करता है। इसके मुख्यत: दो रूप हैं- आर्थिक आधारभूत संरचना एवं सामाजिक आधारभूत संरचना।

आर्थिक आधारभूत संरचना	सामाजिक आधारभूत संरचना
• उत्पादन गतिविधियों में प्रत्यक्ष भूमिका • उत्पादन एवं वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्थित • उदाहरण- सड़क, बिजली आदि	• उत्पादन गतिविधियों में अप्रत्यक्ष भूमिका • उत्पादन व वितरण प्रणाली को बाहर से समर्थन • उदाहरण- शिक्षा, स्वास्थ्य आदि

किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता को आधारभूत संरचना एवं निवेश व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। अत: निवेश को आकर्षित करने हेतु संस्थागत कमियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोशिश करती है।

आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना एक-दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना से आर्थिक संवृद्धि होती है, जबकि सामाजिक आधारभूत संरचना, मानव विकास के साथ सामाजिक विकास को गति प्रदान करती है।

स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार आधारभूत संरचना के विकास हेतु निवेश कर रही थी। किंतु, कमियाँ यथावत् बनी हुई हैं जिनके निवारण हेतु सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का प्रयोग कर रही है।

आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास में संबंध (Relation between Infrastructure and Economic Development)

आधारभूत संरचना तथा आर्थिक विकास चक्रीय रूप से संबंधित होकर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। आधारभूत संरचना जहाँ एक ओर आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास के कारण जीवन स्तर तथा आय में वृद्धि के कारण नए एवं उच्च तकनीकयुक्त उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण अवसंरचना पर निवेश आवश्यक हो जाता है।

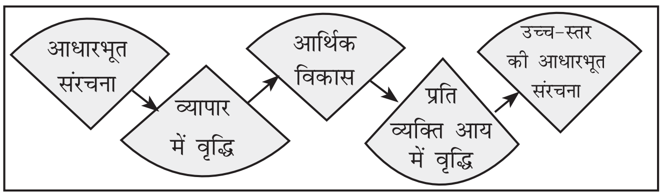

आधारभूत संरचना, आर्थिक विकास को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है–

- निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहन
- उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 8

भारतीय कृषि
(Indian Agriculture)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारतीय कृषि तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका
- 10वीं कृषि गणना, 2015-16
- भारतीय कृषि की विशेषताएँ
- भारतीय कृषि की मुख्य चुनौतियाँ
- स्वतंत्रता के समय और इसके बाद कृषि की स्थिति
- कृषि विकास के लिए नवीन पहल

भारत में भूमि सुधार

- परिचय
- ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणाम
- स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य
- भूमि सुधार की आवश्यकता
- भूमि सुधारों के प्रमुख घटक
- सहकारी कृषि और भूमि सुधार
- भूमि सुधारों की कमियाँ
- भूमि सुधारों के सकारात्मक परिणाम
- भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक
- भूमि सुधार की वर्तमान चुनौतियाँ
- भूदान आंदोलन और भूमि सुधार
- महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार
- नई आर्थिक नीति और भूमि सुधार
- सरकार द्वारा किए गए हालिया उपाय

कृषि सब्सिडी

- परिचय
- कृषि सब्सिडी का औचित्य
- कृषि सब्सिडी के प्रकार
- मूल्य समर्थन नीति
- न्यूनतम समर्थन मूल्य
- उचित एवं लाभकारी मूल्य
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- उर्वरक सब्सिडी
- निर्यात सब्सिडी
- सिंचाई सब्सिडी
- बिजली सब्सिडी
- कृषि अवसंरचना सब्सिडी
- कृषि सब्सिडी की आवश्यकता
- कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दे तथा उनके संभावित समाधान

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- खाद्य सब्सिडी
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- पी.डी.एस. के उद्देश्य
- पी.डी.एस. के कार्य
- पी.डी.एस. का महत्त्व
- पी.डी.एस. की सीमाएँ एवं आलोचना
- पी.डी.एस में सुधार
- खाद्य सुरक्षा
- बफर स्टॉक
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक

कृषि विपणन और संबंधित मुद्दे

- परिचय
- कृषि विपणन की विशेषताएँ
- कृषि विपणन की आवश्यकता
- कृषि विपणन के कार्य
- कृषि विपणन का महत्त्व
- भारत में कृषि विपणन के विकास के चालक
- भारत में कृषि विपणन की समस्याएँ
- बाज़ार विनियमन के उद्देश्य
- भारत में कृषि विपणन की वर्तमान पद्धति
- कृषि मूल्य का स्थिरीकरण
- बाज़ार बिचौलिए
- भारत में कृषि विपणन में सुधार के लिए उठाए गए कदम
- किसान उत्पादक संगठन
- अनुबंध कृषि
- किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

- परिचय
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण की संभावना
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक
- खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बाधाएँ
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पहल

पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था

- भारत में पशुपालन
- भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका
- पशुपालन क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ
- पशुपालन क्षेत्र के विकास हेतु पहल
- डेयरी क्षेत्र
- सहकारिता मंत्रालय
- भारत में सहकारी आंदोलन
- भारत में मत्स्यपालन उद्योग
- मत्स्यपालन के विकास हेतु पहल
- मधुमक्खी-पालन
- मुर्गी-पालन
- एकीकृत कृषि प्रणाली

Copyright @ Sanskriti IAS

इसके साथ ही लोग अपना खाता, जमाबंदी नकल और भू-नक्शा का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।

- इस योजना के तहत राज्य के लोग अपना खसरा नंबर और जमाबंदी नंबर डालकर अपनी भूमि का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं।

भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की राज्य-वार स्थिति

क्र.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	कुल भूमि का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99.5
2	आंध्र प्रदेश	97.1
3	अरुणाचल प्रदेश	0.0
4	असम	76.3
5	बिहार	95.4
6	छत्तीसगढ़	92.4
7	गोवा	100
8	गुजरात	94.7
9	हरियाणा	92.8
10	हिमाचल प्रदेश	98.8
11	जम्मू और कश्मीर	6.4
12	झारखंड	99.5
13	कर्नाटक	99.6
14	केरल	50
15	लक्षद्वीप	100
16	मध्य प्रदेश	100
17	महाराष्ट्र	98.8
18	मणिपुर	15.5
19	मेघालय	0.0
20	ओडिशा	99.9
21	पंजाब	94.9
22	राजस्थान	94.6
23	सिक्किम	100
24	तमिलनाडु	99.7
25	तेलंगाना	99.4
26	उत्तराखंड	94.6
27	उत्तर प्रदेश	96.3
28	पश्चिम बंगाल	98.7

स्रोत : भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार (अप्रैल 2022)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 (Land Acquisition Act, 2013)

भूमि अधिग्रहण क्या है

भूमि अधिग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार (राज्य या संघ) बुनियादी ढाँचे के विकास, शहरीकरण या औद्योगीकरण के उद्देश्य से निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। बदले में सरकार, भूमि के मालिक को बाज़ार मूल्य के अनुसार उचित मुआवज़ा देगी जो भूमि मालिकों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए उपयुक्त है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 ने पुरातन भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित किया है।

भूमि अधिग्रहण के प्रावधान और उद्देश्य

अधिनियम के अनुसार, सरकार (राज्य, साथ ही केंद्रीय) अपने स्वयं के उपयोग के लिए या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि खरीद सकती है। जो इनमें से किसी को भी शामिल कर सकते हैं-

- भारत की राज्य या राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा सेवाओं से संबंधित किसी भी कार्य के लिए, जिसमें राज्य या केंद्र सरकार के दायरे में नौसेना, थल सेना, वायु सेना या अन्य सशस्त्र बल शामिल होते हैं।
- सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए, लेकिन निजी अस्पतालों, निजी शैक्षिक संस्था और निजी होटलों को छोड़कर।
- कृषि या संबद्ध उद्योगों से जुड़ी किसी भी परियोजना के लिए, जैसे- डेयरी, मत्स्यपालन या मांस।
- औद्योगिक गलियारों, विनिर्माण क्षेत्रों या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में सूचीबद्ध अन्य परियोजनाओं के लिए। इसमें खनन गतिविधियाँ भी शामिल हो सकती हैं।
- जल संचयन के लिए, संरक्षण संरचना परियोजनाएँ या गाँव की साइटों के नियोजित विकास या सुधार के लिए।
- सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए।
- नियोजित विकास के लिए, जैसे कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स।
- गरीब या भूमिहीन, या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए आवासीय परियोजनाओं को विकसित करने के लिए।

सहमति का महत्त्व

जब सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है और भूमि प्रतिबंध को नियंत्रित करती है तो सीधे भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक नहीं है। हालाँकि, जब निजी कंपनियों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो प्रभावित परिवारों में से कम-से-कम 80% की सहमति अनिवार्य है। यदि परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित किया जाता है तो 70% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी होगी।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 9

समावेशी विकास (Inclusive Development)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'समावेशी विकास तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- समावेशी विकास के तत्त्व
- समावेशी विकास के आयाम
- भारत में आर्थिक असमानता की स्थिति
- समावेशी विकास का मापन
- समावेशी विकास के लिए सैद्धांतिक उपाय
- भारत के लिए समावेशी विकास का महत्त्व
- भारत में समावेशी विकास से जुड़े मुद्दे
- समावेशी विकास के समक्ष चुनौतियाँ
- समावेशी विकास के उपाय
- समावेशी विकास में नीति आयोग की भूमिका

गरीबी
- परिचय
- गरीबी के प्रकार
- गरीबी मापन हेतु आँकड़े एकत्र करने की विधि
- गरीबी का मापन
- गरीबी के आकलन में चुनौतियाँ
- भारत में गरीबी के कारण
- गरीबी के प्रभाव
- निर्धनता जाल
- गरीबी उन्मूलन के उपाय
- पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन के उपाय
- वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों का गरीबी पर प्रभाव
- गरीबी उन्मूलन में नीति आयोग की भूमिका
- गरीबी उन्मूलन में वित्तीय समावेशन की भूमिका
- गरीबी उन्मूलन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका
- लैंगिक आधार पर गरीबी का वितरण
- भारत में गरीबी उन्मूलन और सतत् विकास लक्ष्य

बेरोज़गारी और श्रम सुधार
- परिचय
- बेरोज़गारी का वर्गीकरण
- भारत में बेरोज़गारी का मापन
- बेरोज़गारी से संबंधित विभिन्न वक्र
- भारत में बेरोज़गारी की वर्तमान स्थिति
- भारत में बेरोज़गारी के कारण
- बेरोज़गारी पर नियंत्रण के उपाय
- बेरोज़गारी के दीर्घकालिक प्रभाव
- रोज़गार सृजन के लिए किए गए प्रयास
- भारत में रोज़गार की प्रवृत्तियाँ
- गिग अर्थव्यवस्था
- भारत में रोज़गार पर वैश्वीकरण का प्रभाव
- श्रम की अवधारणा
- श्रम संबंधी शब्दावलियाँ
- भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता कम होने के कारण
- श्रम सुधार
- श्रम संहिताएँ
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत में श्रम सुधार
- जनसांख्यिकीय लाभांश
- केयर इकोनॉमी

परिचय (Introduction)

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, समावेशी विकास में संवृद्धि की प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों ही महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल होते हैं तथा लोगों के सभी समूह समृद्धि में भागीदारी करते हैं और समान रूप से लाभान्वित होते हैं।
- विश्व बैंक के अनुसार, समावेशी विकास वह गति है जिसके तहत कोई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और इस विकास से प्राप्त लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचता है।
- इस प्रकार, समावेशी विकास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में हो रही वृद्धि और उसके न्यायपूर्ण वितरण से है। न्यायपूर्ण वितरण से आशय ईमानदार और न्याययुक्त वितरण को आम जनता, विशेषकर गरीबों व कमज़ोर वर्गों के लिए सुनिश्चित करना है जिसमें समता, अवसर की समानता एवं बाज़ार की संक्रमणकालीन अवधि में रोज़गार का संरक्षण शामिल है।
- भारत में समावेशी विकास की पहली झलक प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरंभ किए गए 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' में दिखती है। इसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऐसे कार्यक्रमों को चलाया गया जिनका उद्देश्य देश से गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी और अशिक्षा को समाप्त कर समावेशी विकास को प्रोत्साहन देना रहा है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से पहली बार 'तीव्र एवं समावेशी विकास' को लक्ष्य बनाया गया। इसके बाद बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को 'तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास' तक ले जाया गया।

Copyright @ Sanskriti IAS

सामाजिक अपवर्जन (Social Exclusion)

निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन, निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्य शैली है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है।

असुरक्षा (Insecurity)

निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों (जैसे- किसी पिछड़ी जाति के सदस्य) या व्यक्तियों (जैसे- कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना दिखाता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसरों के रूप में उपलब्ध विकल्पों से होता है।

गरीबी के प्रकार (Types of Poverty)

गरीबी के मुख्यतः दो प्रकार हैं-

सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty)

- सापेक्ष गरीबी आय एवं संपत्ति के वितरण की स्थिति को दर्शाती है, अर्थात् यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्षिक रूप से गरीब समाज में लोगों के जीवन स्तर में विषमता देखी जाती है।
- इसके अंतर्गत निर्धनता/गरीबी का आकलन तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, अर्थात् यह विभिन्न वर्गों के मध्य तुलना के आधार पर गरीबी की गणना है।
- सापेक्ष गरीबी, समावेशी विकास की विरोधी है क्योंकि समाज में जितनी अधिक विषमता होगी, समाज उतना कम समावेशी होगा। अर्थात्, यह देश में व्याप्त आर्थिक असमानता की व्याख्या करती है।

<table>
<tr><th>लॉरेंज़ वक्र</th><th>गिनी गुणांक</th></tr>
<tr>
<td>

- सापेक्ष गरीबी मापन की यह विधि वर्ष 1905 में **मैक्स ओ. लॉरेंज़** द्वारा विकसित की गई।
- यह आय विषमता को दर्शाने वाला ग्राफ है।
- पूर्ण समता रेखा (निरपेक्ष समता रेखा) एक मानक/काल्पनिक रेखा है। वास्तविक आँकड़ों पर आधारित लॉरेंज़ वक्र इस समता रेखा से जितनी अधिक दूर होगी, विषमता उतनी अधिक होगी, जैसा कि रेखाचित्र में प्रदर्शित है।

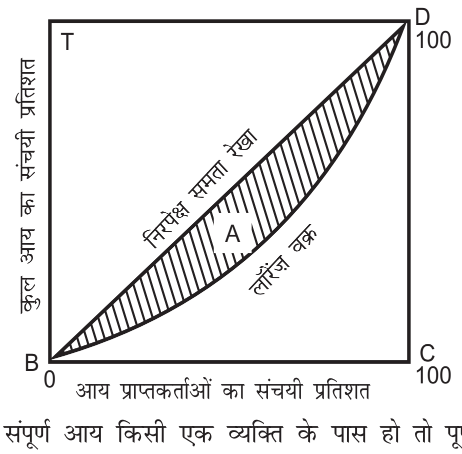

- यदि संपूर्ण आय किसी एक व्यक्ति के पास हो तो पूर्ण असमान आय वितरण होगा और इसे प्रदर्शित करने वाली रेखा BT होगी।
- वहीं, आदर्श स्थिति में निरपेक्ष समानता रेखा एवं लॉरेंज़ वक्र के बीच कोई दूरी नहीं होती। इसे प्रदर्शित करने वाली रेखा BD होगी।

</td>
<td>

- सापेक्ष गरीबी मापन की यह दूसरी विधि है जो कि लॉरेंज़ वक्र पर आधारित ग्राफ है।
- इस गुणांक को **कोरेडो गिनी** ने विकसित किया था। यह गुणांक राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति में विषमता की गणितीय माप प्रस्तुत करता है।
- यह देश में उपस्थित जनसंख्या के मध्य आय का वितरण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात् यह आर्थिक असमानता की डिग्री को व्यक्त करता है।
- यह वास्तविक लॉरेंज़ वक्र और निरपेक्ष समता रेखा के बीच का छायांकित क्षेत्रफल (A) तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल (BCD) के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है।

$$\text{गिनी गुणांक (G)} = \frac{\text{छायांकित क्षेत्रफल (A)}}{\text{समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल (BCD)}}$$

- गिनी गुणांक (G) में 100 से गुणा करने पर गिनी सूचकांक प्राप्त हो जाएगा।
- यदि $G = 0$ है तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्राप्त हो रही है और यदि $G = 1$ है तो इसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति को पूरी आय प्राप्त हो रही है। गिनी गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है।

</td>
</tr>
</table>

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 10 — उद्योग (Industries)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'उद्योग तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- उद्योगों का विकास
- औद्योगिक नीतियाँ
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण
- भारत में औद्योगिक वित्त
- भारत में औद्योगिक रुग्णता
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- परिचय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का महत्त्व
- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र से संबंधित प्रमुख संगठन
- लघु उद्योगों का वित्तीयन
- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में सुधार हेतु यू.के. सिन्हा समिति
- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम
- केंद्रीय बजट 2024-25 में एम.एस.एम.ई. के लिए पहल

ई-कॉमर्स
- परिचय
- ई-कॉमर्स के लाभ
- ई-कॉमर्स के प्रकार
- ई-कॉमर्स से संबंधित मॉडल
- भारतीय अर्थव्यवस्था में ई-कॉमर्स का योगदान
- ई-कॉमर्स नीति की आवश्यकता
- भारत में ई-कॉमर्स के समक्ष चुनौतियाँ
- ई-कॉमर्स क्षेत्र में सुधार हेतु किए गए प्रयास

सेवा क्षेत्र
- परिचय
- सेवा क्षेत्र का महत्त्व
- भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि के कारण
- भारत में सेवा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ
- सेवा क्षेत्र के विकास हेतु किए गए प्रयास

परिचय (Introduction)

- उद्योग शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन, खनन, पशु-प्रजनन एवं पालन और वनस्पति संबंधी क्रियाओं, निर्माण व विनिर्माण संबंधी क्रियाओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है।
- व्यापक अर्थों में उद्योग का आशय वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों के समूह से है। उदाहरण के लिए, रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने वाली सभी इकाइयों को उद्योग कहते हैं। इन्हीं के समकक्ष बैंकिंग तथा बीमा आदि भी उद्योग कहलाते हैं।
- औद्योगिक क्षेत्रक के अंतर्गत संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने की क्षमता विद्यमान होती है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- उद्योगों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है– प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग एवं तृतीयक या सेवा उद्योग। प्राथमिक उद्योग में कृषि, पशुपालन, खनन आदि आते हैं। द्वितीयक उद्योग में निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग शामिल होते हैं। निर्माण उद्योग भौतिक संरचनाओं (सड़क, मकान आदि) का निर्माण करता है जबकि विनिर्माण उद्योग कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करता है। तृतीयक उद्योग में वित्त, बीमा, परिवहन, पर्यटन आदि सेवाएँ शामिल होती हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने और रोज़गार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह आर्थिक विकास का सूचक/इंजन माना जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल जी.वी.ए. में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 27.6% है।

उद्योगों का महत्त्व
- जी.डी.पी. में योगदान
- रोज़गार सृजन में योगदान
- विदेशी व्यापार में योगदान

उद्योगों का विकास (Development of Industries)

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उद्योगों का विकास (Development of Industries in India before Independence)

- औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना ने अपने पिछड़ेपन का प्रदर्शन किया। औपनिवेशिक शासन से पूर्व

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 11

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- व्यष्टि अर्थशास्त्र
- मांग की अवधारणा
- मांग का नियम
- मांग की लोच
- पूर्ति
- उपयोगिता की अवधारणा
- उत्पादन फलन की अवधारणा
- पैमाने के प्रतिफल
- उत्पादन संभावना वक्र
- राजस्व/संप्राप्ति/आगम/आय की अवधारणा
- लागत का सिद्धांत
- बाज़ार

परिचय (Introduction)

अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उनके वितरण एवं उनके उपभोग से है। अर्थशास्त्र को सामान्यत: को दो शाखाओं में बाँटा जाता है- व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ
- व्यष्टि अर्थशास्त्र
- समष्टि अर्थशास्त्र

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)

- इसे 'सूक्ष्म अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के एक भाग के रूप में आर्थिक संबंधों, समस्याओं अथवा मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग अथवा एक बाज़ार आदि।
- व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि बाज़ार में व्यक्तियों की अंत:क्रिया द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा एवं कीमत किस प्रकार निर्धारित होती हैं।

व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख घटक
- उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत
- उत्पादक व्यवहार सिद्धांत
- कीमत सिद्धांत

उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत (Theory of Consumer Behaviour)

इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न घटकों में आवंटित करता है, ताकि अधिकाधिक संतुष्टि/सुख अर्जित किया जा सके।

उत्पादक व्यवहार सिद्धांत (Theory of Producer Behaviour)

इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उत्पादक यह विचार करता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितना करना है, ताकि अधिकाधिक लाभ अर्जित किया जा सके।

कीमत सिद्धांत (Theory of Price)

वास्तव में, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)	समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics)
• यह छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों एवं समस्याओं से संबंधित है, जैसे– एक व्यक्ति, एक गृहस्थ, एक फर्म, एक उद्योग इत्यादि। • यह व्यष्टि आर्थिक चरों, जैसे– उपभोक्ता की मांग और उत्पादक द्वारा आपूर्ति इत्यादि का उपयोग करता है। • इसकी केंद्रीय समस्या संसाधनों का आवंटन है।	• यह समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालता है, जैसे– रोज़गार, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट इत्यादि। • यह समष्टि आर्थिक चरों, जैसे– समग्र मांग और समग्र पूर्ति का उपयोग करता है। • इसकी केंद्रीय समस्या राष्ट्रीय आय तथा रोज़गार का निर्धारण है।

Copyright @ Sanskriti IAS

मांग की कीमत लोच (Price Elasticity of Demand)

जब वस्तु की मांग में परिवर्तन को वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे 'मांग की कीमत लोच' कहते हैं।

$$\text{अतः, कीमत लोच} = \frac{\text{मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

$$= \frac{\text{मांगी गई मात्रा में परिवर्तन}}{\text{आरंभ में मांगी गई मात्रा}} \times \frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{आरंभिक कीमत}}$$

यदि वस्तु की कीमत को P से तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा को Q से एवं ΔP और ΔQ द्वारा क्रमशः कीमत व मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को प्रदर्शित किया जाए, तब–

$$\text{मांग की कीमत लोच } (e_P) = \frac{P}{Q} \times \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

कीमत लोच के प्रकार (Types of Price Elasticity)

शून्य मांग की लोच ($e_p = 0$)

यदि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन न आए तो इस स्थिति को शून्य मांग की लोच कहते हैं। इसे निम्नलिखित मांग वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है–

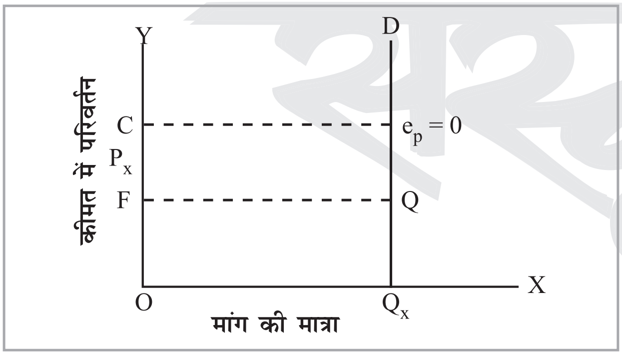

अनंत मांग की लोच ($e_P = \infty$)

यदि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में अनंत परिवर्तन आ जाए तो इस स्थिति को अनंत मांग की लोच कहते हैं। इसे निम्नलिखित मांग वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है–

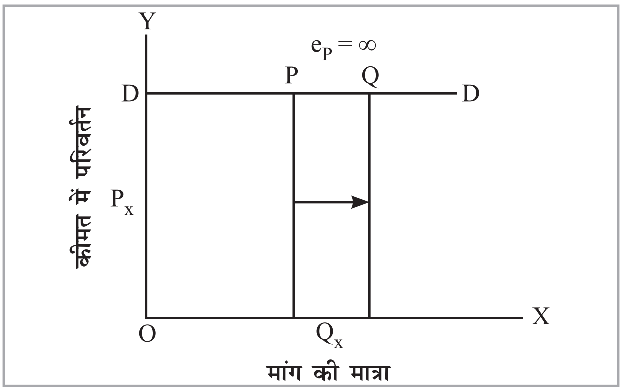

इकाई लोच ($e_P = 1$)

यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन उस अनुपात में हो जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा हो तो इस स्थिति को इकाई लोच कहते हैं। इसे निम्नलिखित मांग वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है–

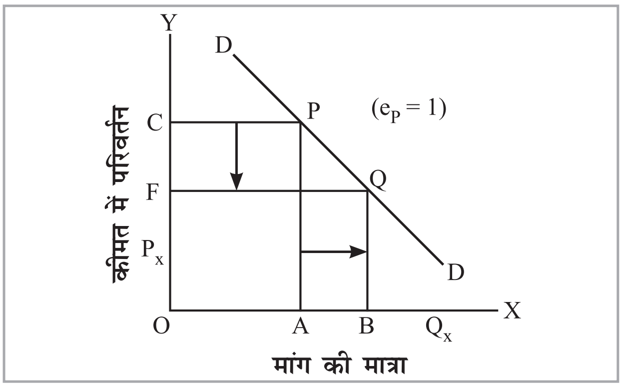

इकाई से अधिक लोच ($e_P > 1$)

यदि वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन कीमतों में थोड़े परिवर्तन के फलस्वरूप हो तो ऐसी स्थिति को इकाई से अधिक लोच कहते हैं। इसे निम्नलिखित मांग वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है–

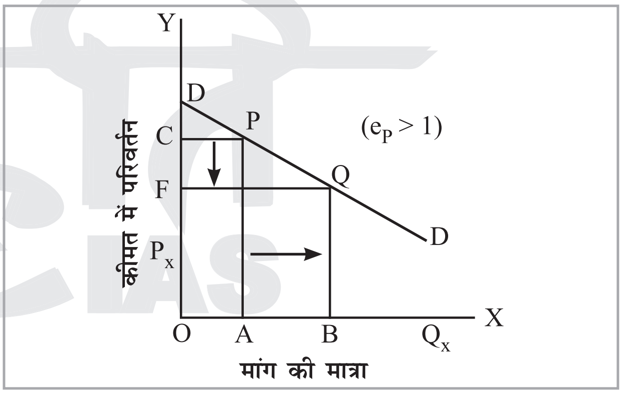

इकाई से कम लोच ($e_P < 1$)

यदि कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में बहुत कम परिवर्तन आए तो इस स्थिति को इकाई से कम लोच कहते हैं। इसे निम्नलिखित मांग वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है–

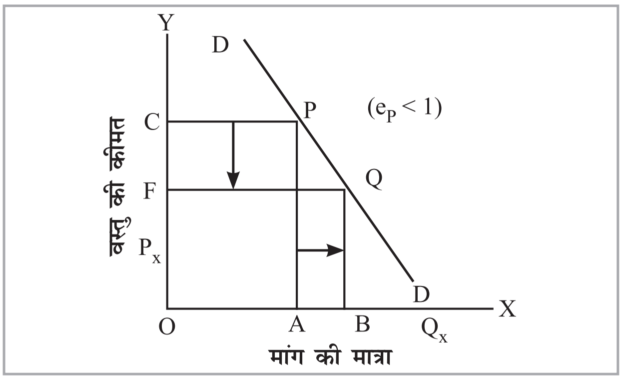

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 12

अंतर्राष्ट्रीय संगठन
(International Organizations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

विश्व बैंक
- परिचय
- विश्व बैंक समूह
- विश्व बैंक समूह की प्रशासनिक संरचना, उद्देश्य एवं कार्य
- विश्व बैंक समूह की सदस्यता
- विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट
- विश्व बैंक समूह और भारत

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- परिचय
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत
- आई.एम.एफ. के कोटा और प्रशासन में सुधार

विश्व व्यापार संगठन
- परिचय
- विश्व व्यापार संगठन की संरचना, सिद्धांत एवं उद्देश्य
- विश्व व्यापार संगठन की गतिविधियाँ, कार्य एवं महत्त्व
- विश्व व्यापार संगठन से संबंधित समझौते
- विश्व व्यापार संगठन के सुरक्षोपाय
- विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन
- विश्व व्यापार संगठन और भारत

खाद्य एवं कृषि संगठन
- परिचय
- खाद्य एवं कृषि संगठन के कार्य
- खाद्य एवं कृषि संगठन और भारत

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
- परिचय
- ओ.ई.सी.डी. के उद्देश्य
- ओ.ई.सी.डी. और भारत

विश्व बैंक (World Bank)

परिचय (Introduction)

- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) को संयुक्त रूप से 'विश्व बैंक' के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य देशों को विकासात्मक कार्यों से संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- विश्व बैंक समूह एवं विश्व बैंक की शुरुआत आई.बी.आर.डी. की स्थापना से हुई थी। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता एवं सलाह देते हैं।

विश्व बैंक समूह (World Bank Group)

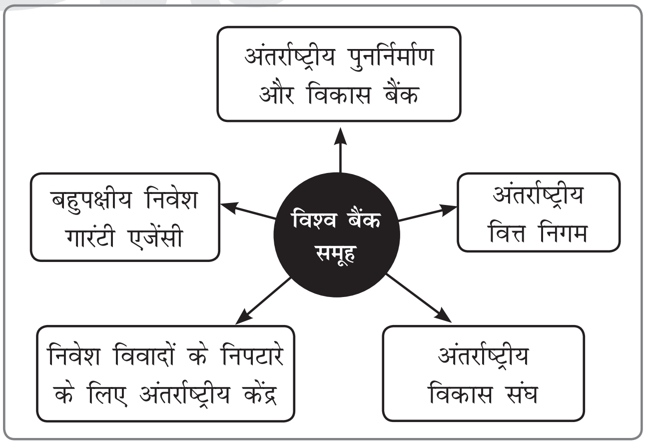

पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD)

- आई.बी.आर.डी. की स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- प्रारंभ में इसका उद्देश्य पिछड़े और विकासशील देशों को ऋण व गैर-उधार सेवाओं (अनुदान) के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देना था, साथ ही देश के विकास से संबंधित रणनीति एवं सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना था।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 13 पूंजी बाज़ार (Capital Market)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'पूंजी बाज़ार तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- पूंजी बाज़ार के प्रकार
- प्रतिभूतियाँ
- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड
- स्टॉक एक्सचेंज
- वस्तु बाज़ार
- डिपॉजिटरी रसीद
- डेरिवेटिव्स
- महत्त्वपूर्ण शब्दावलियाँ
- निधि प्रबंधन गतिविधियाँ
- व्यावसायिक संगठन
- कंपनी अधिनियम
- क्रेडिट रेटिंग
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण
- बीमा
- बीमा का महत्त्व
- बीमा के प्रकार
- बीमा कंपनियाँ
- पुनर्बीमा
- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
- बीमा लोकपाल
- बीमा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल
- भारत में बीमा क्षेत्र की स्थिति
- पेंशन
- भारत में पूंजी बाज़ार का नियामक ढाँचा
- पूंजी बाज़ार सुधार

परिचय (Introduction)

- पूंजी बाज़ार वित्तीय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। पूंजी बाज़ार शब्द संस्थागत व्यवस्था या प्रबंध को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से दीर्घकालिक निधि, ऋण एवं इक्विटी दोनों ही, एकत्रित एवं निवेशित की जा सकती हैं।
- पूंजी बाज़ार का मुख्य कार्य समुदाय की बचतों को औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों तथा अन्य राजकीय प्रयोग के लिए उपलब्ध कराना है। दूसरे शब्दों में, बचत आधिक्य वाले क्षेत्रों से बचत प्राप्त करके बचत की मांग वाले क्षेत्रों या उत्पादक क्षेत्रों तक उसे पहुँचाने का कार्य पूंजी बाज़ार द्वारा किया जाता है।

पूंजी बाज़ार के प्रकार (Types of Capital Market)

पूंजी बाज़ार को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है–

- गिल्ट-एज्ड बाज़ार
- विकास वित्त संस्थान
- औद्योगिक प्रतिभूति बाज़ार

गिल्ट-एज्ड बाज़ार (Gilt-edged Market)

गिल्ट-एज्ड बाज़ार को सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समर्थित सरकारी और अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार को संदर्भित करता है। ये प्रतिभूतियाँ जोखिम-मुक्त और अत्यधिक तरल होती हैं, इसलिए इन्हें सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियाँ कहा जाता है।

गिल्ट-एज्ड बाज़ार में निवेशक मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक, एल.आई.सी., जी.आई.सी. और भविष्य निधि जैसे संस्थान हैं। आर.बी.आई. अपने 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स' के माध्यम से गिल्ट-एज्ड बाज़ार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

गिल्ट-एज्ड बाज़ार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है– ट्रेज़री बिल बाज़ार और सरकारी बॉण्ड बाज़ार। ट्रेज़री बिल सरकार के वित्त की अल्पकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि सरकारी बॉण्ड दीर्घकालिक विकास व्यय के वित्तपोषण के लिए जारी किए जाते हैं।

विकास वित्त संस्थान (Development Finance Institutions)

विकास वित्त संस्थान लंबी अवधि तक चलने वाले पूंजी-गहन निवेशों के लिए दीर्घकालिक और कम दरों पर ऋण प्रदान करते हैं, जैसे– शहरी बुनियादी ढाँचा, खनन, भारी उद्योग तथा सिंचाई प्रणाली आदि।

भारत में पहला विकास वित्त संस्थान (डी.एफ.आई.) वर्ष 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) की स्थापना के साथ शुरू हुआ था।

वर्तमान में, आर.बी.आई. द्वारा विनियमित अखिल भारतीय वित्त संस्थान (ए.आई.एफ.आई.) के रूप में देश में केवल पाँच वित्तीय संस्थान कार्यरत हैं– नाबार्ड, सिडबी, एक्ज़िम बैंक, एन.एच.बी. और एन.ए.बी.एफ.आई.डी.।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 14	आयोजन (Planning)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'आयोजन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- आयोजन के प्रकार
- भारत में आयोजन
- भारत में आयोजन के उद्देश्य
- भारत में आयोजन की उपलब्धियाँ
- योजना आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद्
- भारत में आयोजन की विफलता के कारण

नीति आयोग
- परिचय
- नीति आयोग का गठन
- नीति आयोग की संरचना
- नीति आयोग के उद्देश्य
- नीति आयोग के कार्य
- सहकारी संघवाद
- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद
- पंद्रह-वर्षीय विज़न डॉक्यूमेंट
- न्यू इंडिया @75 के लिए कार्यनीति
- राज्य सहायता मिशन
- 21वीं सदी के लिए कृषि संबंधी चुनौतियाँ और नीतियाँ
- शून्य अभियान
- नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर

विकसित भारत @2047
- परिचय
- विकसित भारत विजन के समक्ष चुनौतियाँ
- विकसित भारत के लिए रोडमैप

परिचय (Introduction)

- आयोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राष्ट्र के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है।
- योजना आयोग ने 'आयोजन' को इस प्रकार परिभाषित किया है– "आयोजन अनिवार्य रूप से परिभाषित सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न साधनों से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने की संगठित और उपयोगी प्रणाली है।"
- आयोजन के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं–
  - ➤ लक्ष्य निर्धारण
  - ➤ लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाई गई पद्धतियाँ
  - ➤ उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन संबंधी ज्ञान
- आर्थिक आयोजन की महत्ता के कारण ही इसे संविधान की समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) में उल्लिखित किया गया है।

आयोजन के प्रकार (Types of Planning)

ध्यातव्य है कि आयोजन को पहली बार सोवियत संघ में अपनाया गया था। तत्पश्चात् कई अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया, किंतु इनके द्वारा इसको लागू किए जाने में काफी विभेद देखा गया। इन विभेदों के आधार पर आयोजन को निम्नलिखित प्रकारों में बाँटा जा सकता है–

आदेशात्मक आयोजन (Directive Planning)

आदेशात्मक आयोजन से तात्पर्य राज्य द्वारा नियंत्रित आयोजन से है। यह अधिकांशत: समाजवादी या साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है।

विशेषताएँ (Features)

- यह एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य की प्रत्यक्ष और व्यापक भूमिका होती है। विदित है कि यह प्रारूप रूस एवं चीन में अपनाया गया है।
- इस प्रकार के आयोजन हेतु विस्तृत प्रशासनिक ढाँचा विकसित किया जाता है।
- इसमें प्रशासनिक तंत्र द्वारा मूल्यों का निर्धारण भी किया जाता है जिसे 'प्रशासित कीमत निर्धारण तंत्र' (Administered Pricing Mechanism) की संज्ञा दी जाती है।
- इसमें राज्य की भूमिका नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर होती है।
- इसमें प्रशासन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित होने के कारण इसे 'लक्ष्य आधारित आयोजन' भी कहा जाता है।
- उक्त कार्यों के लिए केंद्रीय स्तर पर एक संस्था होती है जिसका उत्तरदायित्व योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन करना है।

निर्देशात्मक आयोजन (Indicative Planning)

निर्देशात्मक आयोजन का अभिप्राय विकेंद्रीकृत आयोजन से है, अर्थात् इस प्रकार के आयोजन में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। ध्यातव्य है कि इसमें भी एक शीर्ष संस्था होती है जिसके द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 15 सतत् विकास (Sustainable Development)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'सतत् विकास तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- सतत् विकास की अवधारणा
- सतत् विकास के आधारभूत सिद्धांत
- सतत् विकास के उद्देश्य
- हरित अर्थव्यवस्था
- सतत् विकास के समक्ष चुनौतियाँ
- सतत् विकास लक्ष्य-2030
- सतत् विकास लक्ष्य और सरकार के प्रयास
- भारत में सतत् विकास
- सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक
- वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट

सतत् विकास की अवधारणा (Concept of Sustainable Development)

- सतत् विकास से अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। सतत् विकास की अवधारणा आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर बल देती है।
- सतत् विकास की अवधारणा का वास्तविक विकास वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर' (ब्रंटलैंड रिपोर्ट) आने के बाद हुआ। ब्रंटलैंड रिपोर्ट (Brundtland Report) द्वारा सतत् विकास को 'भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने वाले विकास' के रूप में वर्णित किया गया है।
- हालाँकि, सतत् विकास की अवधारणा को समुचित महत्त्व ब्राज़ील में वर्ष 1992 में हुए 'रियो पृथ्वी सम्मेलन' [इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संधि पर सहमति बनी जिसे 'यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज' (UNFCCC) कहते हैं] तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों द्वारा मिला।
- सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, जो एक नैतिक प्रश्न है। अत: वर्तमान पीढ़ी का नैतिक दायित्व है कि वह ऐसे विकास का संवर्द्धन करे, जो कि प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने के साथ-साथ प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करने, विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था की पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा करने तथा भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर पड़ने वाले संभावित अतिरिक्त जोखिम को हटाने के अनुकूल हो।

सतत् विकास के आधारभूत सिद्धांत (Fundamental Principles of Sustainable Development)

नवीकरणीयता (Renewability)

नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल धारणीय आधार पर हो, ताकि किसी भी स्थिति में उपभोग की दर, पुनर्सृजन की दर से ज़्यादा न हो।

अनुकूलनशीलता (Adaptability)

एक सतत् रूप से विकासशील समाज बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को नई-नई तकनीकों एवं आविष्कारों के माध्यम से बदलने की क्षमता रखता है।

प्रतिस्थापन (Substitution)

गैर-नवीकरणीय संसाधनों की अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। सतत् विकास में गैर-नवीकरणीय संसाधनों का प्रतिस्थापन नवीकरणीय संसाधनों द्वारा किया जाता है।

संस्थागत प्रतिबद्धता (Institutional Commitment)

इसमें सभी नीतियाँ, संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक इच्छा-शक्ति, कानूनी रूपरेखा और वैधानिक संस्थाओं के मध्य आपसी समन्वय को शामिल किया जाता है, जिनके बिना सतत् विकास को संभव नहीं बनाया जा सकता।

अंतर-निर्भरता (Interdependence)

एक सतत् समाज ऐसे संसाधनों का आयात नहीं करता है, जिससे संबंधित समुदाय वंचना का शिकार हो जाए और न ही अपने यहाँ के प्रदूषकों का अन्य समाजों में स्थानांतरण करता है। इस प्रकार, परस्पर अंतर-निर्भरता से सभी समाज लाभान्वित होते हैं।

सतत् विकास के उद्देश्य (Objectives of Sustainable Development)

- सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना तथा विकास के तीनों पहलुओं; अर्थात् सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना।
- भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
- लोग, ग्रह, शांति, संपन्नता और साझेदारी (P5 - People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership) पर विशेष बल देना।

हेड ऑफिस : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र. ✆ 9555-124-124

Copyright @ Sanskriti IAS

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

प्रत्येक माह नया बैच आरंभ

हाइब्रिड कोर्स
ऑफलाइन + ऑनलाइन

SPECIAL OFFER
9555 124 124

दिल्ली एवं प्रयागराज

इतिहास
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

वैकल्पिक विषय
कार्यक्रम विशेषताएँ
- इतिहास और भूगोल में मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

भूगोल
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

GS EXTENSIVE COURSE Prelims + Mains
- लगभग 650 कक्षाओं का एक्स्टेंसिव स्टडी प्रोग्राम
- AI द्वारा समर्थित अध्यापन प्रविधि का प्रयोग
- प्रत्येक टॉपिक का बेसिक से एडवांस लेवल तक कवरेज

INDIVIDUAL MENTORING
- शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाने का प्रशिक्षण
- उत्तर लेखन में सुधार के लिए पर्सनल गाइडेंस
- स्टडी इम्प्रूवमेंट के लिए वन-टू-वन सेशन

PRELIMS GUIDANCE Programme (PGP)
- प्रत्येक टॉपिक के लिए महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स सिनॉप्सिस
- विगत 13 वर्षों के PYQs में पैटर्न के अनुरूप संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीज़न

PCS COURSES
- UPPCS फाउंडेशन कोर्स
- BPSC फाउंडेशन कोर्स
- MPPCS फाउंडेशन कोर्स
- RAS फाउंडेशन कोर्स
- UP-RO/ARO

MAINS MENTORSHIP Programme (MMP)
- संस्कृति IAS की कोर फैकल्टी द्वारा Daily पर्सनल मेंटरिंग की सुविधा
- चारों प्रश्नपत्रों पर आधारित 70 टेस्ट का Intensive Test Programme

INTERVIEW GUIDANCE Programme (IGP)
- एक्सपर्ट के साथ वन-टू-वन सेशन
- DAF एनालिसिस एक्सपर्ट के साथ सीधा संवाद
- इंटरव्यू पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू सेशन्स

CSAT COURSE
- गणित और रीज़निंग का बेसिक से एडवांस लेवल तक Step-by-Step अध्यापन
- कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को सटीक और त्वरित ढंग से हल करने के लिए डायनमिक मेथडलॉजी

NCERT COURSE
- प्रत्येक विषय की कक्षा 6 से 12 तक की NCERT पर कक्षानुसार लैक्चर
- NCERT पर आधारित प्रिलिम्स और मेन्स के प्रश्नों पर चर्चा

QAD PROGRAMME
- GS के सभी टॉपिक्स के विगत वर्षों के PYQs पर विस्तृत प्रश्नोत्तर चर्चा
- प्रिलिम्स परीक्षा में जटिल प्रश्नों को सुगमता से हल करने में सक्षम बनाना

CURRENT AFFAIRS Programme
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक घटनाक्रमों का विस्तृत कवरेज
- फैकल्टी द्वारा समसामयिक घटनाक्रमों का विषयवार डिस्कशन

Mode of Courses
- Hybrid Course — Offline Classroom & Online Live Stream
- Offline Classroom
- Online Live Stream — 3 साल तक Mobile App पर वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

sanskritiias.com
Follows us: YouTube